

जनता को तंग करने वाले फैसले



पता नहीं यह निकाय किस आधार पर इस नतीजे पर पहुंच गया कि 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के इंजन ऐसे हो जाते हैं कि उनका उत्सर्जन इतना बढ़ जाता है कि वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनता है। इस नतीजे पर पहुंचने के पहले अध्ययन एवं विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया ही गया होगा, लेकिन शायद इसकी अनदेखी कर दी गई कि कई वाहन मालिक अपने वाहनों का कम हमेसान करते हैं।

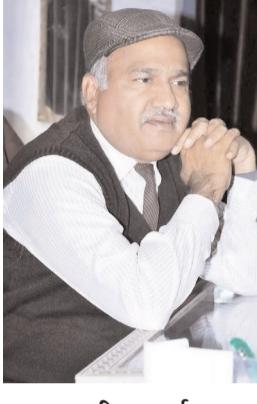
इस्तानाल प्र अधिकतर उन्हें

कमर्शियल इस्टेमेन्ट भी नहीं करते। इसके चलते उनके वाहनों के इंजन इतने खराब नहीं होते कि उन्हें प्रदूषण फैलाने का दोषी मान लिया जाए। कुल लोगों के पास तो ऐसे वाहन हैं, जो 10 साल में 50 हजार किमी भी नहीं चले होते। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार अपनी वाहन नीति में फेरबदल करती रही है, पर उससे वायु प्रदूषण से निपटने में सफलता नहीं मिली। उत्तर भारत और विशेष रूप से राजधानी दिल्ली एवं उसके आसपास के इलाकों...

हा ल म राजथाना म वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के इस आदेश ने दिल्ली एवं एनसीआर के लाखों वाहन मालिकों के लिए परेशनी पैदा कर दी कि उम्र पूरी कर चुके अर्थात् 10 वर्ष से पुराने डीजल और 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह आदेश इसलिए दिया गया, क्योंकि ऐसे वाहनों को चलन से बाहर करने के उसके आदेश पर अमल नहीं किया जा रहा था। ऐसे वाहनों को पेट्रोल-डीजल न देने के फैसले से दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों पर अफरातफरी फैल गई। एक-दो दिन के अंदर ही यह एक राजनीतिक मसला बन गया और ऐसी आवाजें भी उठीं कि उम्र पूरी कर चुके वाहनों को एकाएक ईंधन न देने का फैसला सही नहीं है। खुद दिल्ली सरकार को आगे आना पड़ा और सीएक्यूएम से कहना पड़ा कि वह अपना फैसला वापस ले। प्रदूषण रोधी निकाय सीएक्यूएम के पास पूरे राष्ट्रीय राजथानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता के प्रबंधन का अधिकार है। पता नहीं यह निकाय किस आधार पर इस नतीजे पर पहुंच गया कि 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के इंजन ऐसे हो जाते हैं कि उनका उत्सर्जन इतना बढ़ जाता है कि वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनता है। इस नतीजे पर पहुंचने के पहले अध्ययन एवं विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया ही गया होगा, लेकिन शायद इसकी अनदेखी कर दी जाई कि कई वाहन मालिक अपने वाहनों का कम इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर उनका कमर्शियल इस्तेमाल भी नहीं करते। इसके चलते उनके वाहनों के इंजन इतने खराब नहीं होते कि उन्हें प्रदूषण फैलाने का दोषी मान लिया जाए। कुछ लोगों के पास तो ऐसे वाहन हैं,

धूल, धूप के लिए जान जात ह। जहा सड़कों के किनारे फुटपाथ होते हैं, उनका उपयोग पैदल यात्री छोड़कर अन्य सब करते हैं। कहीं पार्किंग होती है और कहीं छोटी-मोटी दुकान लगी होती है। चूंकि अतिक्रमण से ग्रस्त फुटपाथों पर पैदल यात्री नहीं चल पाते, इसलिए वे मजबूरी में सड़कों पर चलते हैं। इससे सड़कों पर वाहनों का चलना और धीमा हो जाता है। इसका नतीजा जाम और वाहनों का उत्सर्जन होता है। इस स्थिति से सब अवगत हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देने से इन्जनियर किया जा रहा है। वाहनों के खराब इंजन के चलते उनसे निकलने वाले उत्सर्जन को मापने के जो तौर-तरीके प्रचलित हैं और जिसके तहत पेट्रोल पांपों से वाहन चालक सर्टिफिकेट लेते हैं, वे फेल हो चुके हैं। एक तो लोग ऐसे सर्टिफिकेट लेने की परवाह नहीं करते और दूसरे, वाहन का इंजन चाहे जैसा हो, मनवाहा सर्टिफिकेट पैसे देकर भिल ही जाता है। होना यह चाहिए कि वाहनों के जो भी सर्विस सेंटर, वर्कशाप या सड़क किनारे के मैकेनिक हैं, उनके पास ऐसे उपकरण हों कि वे वाहनों के उत्सर्जन की भी ढंग से जांच-परख कर सकें। यह नियम बनना चाहिए कि ये सब अपने पास आएं किसी भी वाहन के उत्सर्जन को हर हाल में नियन्त्रित करें। उन्हें वाहन की हर तरह की कमी दूर करने और उनके ठीक हालात में होने का सर्टिफिकेट देने का भी अधिकार होना चाहिए। इस अधिकार की निगरानी वाहन निर्माता कंपनियों और सरकार को संयुक्त रूप से करनी चाहिए। वे आसानी से यह काम कर सकती हैं। वाहन निर्माता कंपनियों के पास मुनाफे के साथ सीएसआर फंड भी होता है।

ग्रामीण समाज में अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें बचपन से लेकर जवानी तक साथ-साथ पते-बढ़े भाइयों तक के बीच में किसी बहुत माझूरी-सी बात को लेकर अनुबन्ध हो जाती है। छोटी-सी बात कब बड़ी बन जाती है, पता ही नहीं चलता। ऐसे में दोनों के बीच जिस तरह बातचीत बढ़ हो जाती है, वह वक्त कब दिन, महीनों से साल दर



विजय गग

करता फिर मैं क्यों कहूँ? छोटी-छोटी शिकवे-शिकायतों का यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। फोन हाथ में है और दोस्त को बस लगाना ही तो है। फिर हम अपने आपको बटन दबाने से रोक क्यों लेते हैं? ऐसा नहीं है कि यह मनोभाव एक ही व्यक्ति के मन में उमड़ती -युमड़ती रहती होगी। सभी इसान ही हैं। ये ऐसी भावनाएँ हैं जो सबके अंदर में आती-जाती हैं। बस उसका बरसना बाकी रह जाता है। ऐसी घटनाएँ नकारात्मक तरीके से व्यक्ति के मन में परत-दर-परत जमती जाती हैं और आखिर मैं ये किसी पहाड़ से भी बड़े स्वरूप का आकार ले लेती हैं। ये कहीं दिखती नहीं हैं, लेकिन मन में जरूर खड़ी रहती हैं और कई बार खुब्ज़स, रेजिस्ट्रेशन, प्रतिशोध सहित तमाम बुराइयों को जमन देती हैं। कई बार मन के भीतर प्रेम रहते हुए भी लोग इससे सख्त व्यवहार करते हैं कि उनका अहंकार उनके वास्तविक भाव पर हावी होता है। वे अपने भीतर बसे या ऐसे प्रेम का, भावना का प्रकटीकरण नहीं कर पाते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अखिले ऐसा क्यों होता है? लोग मन में बसे अहं के अदृश्य दीवार को भिस क्यों नहीं पाते हैं? अपनी भावना को मन के भीतर कैद करने से घुटन तो जरूर होती होगी। फिर लोग इससे निजात क्यों नहीं पाना चाहते हैं? लोग खुद से क्यों लड़ते रहते हैं? शायद ऐसे लोग यह सोचते होंगे कि बात होगी तो यह कहूँगा, यह शिकायत भी कर दूंगा और प्रेम की बातें भी प्रकट कर दूंगा, लेकिन जब आमने-सामने आ हैं तो वे तमाम बातें जुबान तक नहीं आ पाते हैं। मन के भीतर ही दबी रह जाती है। भावना को सही तरीके से और सही समय पर प्रकट नहीं किए जाने के कारण आज के दौर में अवसाद के कई मामले सामने आ रहे हैं। अस्पतालों के अवसाद विभाग में बढ़ती मरीजों की संख्या इस बात की गवाही देती नजर आती है। कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, जो बताते हैं कि मेरे किसी परिजन या रिशेदोर का निधन हो गया... उनसे 'बहुत स्वेच्छा था... उनसे मैं बहुत कुछ कहना चाहता था... बचपन में उनके कांथे चढ़ कर खेलता था... उनके साथ उनकी थाली में बैठ कर खाना खा लेता था। लेकिन किसी दिन 'हम बड़ा तो हम बड़ा जैसी एक छोटी-सी बात को लेकर हम लोगों में तकरार बढ़ती गई' और हम लोग दूर होते गए। अब मैं भी अधें हो गया हूँ और उनका तो निधन ही हो गया। काश वे मुझे एक बार मिलते तो दिल की सारी बातों को खोलकर उनके सामने रख देता, लेकिन अब यह संभव नहीं है। जब तक तक थे, तब तक कहा नहीं, अब कहना चाहता हूँ तो वे ही नहीं। विडंबना यह है कि ऐसे लोग खुद पहल करके समय को थाम नहीं लेते और बाद में बस अफसोस करते रह जाते हैं। भावना को मन में दबाने के बजाय हम उसे समय पर और सही तरीके से बिना अहंकार के किसी के सामने प्रकट करें, क्या यह संभव नहीं है? अगर ऐसा ही है तो हमें करना चाहिए, क्योंकि यह अच्छा है। इससे हम मन ही मन लड़ने, घृणने और अवसाद में रखने के बजाय खुली हवा में सांस ले सकेंगे, खुश रह सकेंगे। व्यक्ति अपने मन को खोल कर देखे, सहज-सरल बन कर देखे... विवेक के साथ स्थितियों का आकलन करते हुए भावनाओं को प्रकट करके देखे। निश्चित तौर पर यह सकारात्मकता को बढ़ावा देगा और आखिरकार उसके लिए किसी तरह से अच्छा ही साबित होगा। अच्छे या बुरे की ऊहापोह को दूर करेगा। यों भी, किसी से किसी बात पर अनबन हो गई है तो देखने की जरूरत यह है कि क्या वह कोई ऐसी बात थी, जिससे दूसरे की गरिमा और जीवन को स्थायी हानि हुई! अगर नहीं, तो दुनिया के चलते रहने की दूरिं से जीवन को भी सहज बनाना चाहिए और बीती बातों को भुला कर नए सिरे से जीवन को ऐसे अहसास देने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें मानवीयता के मूल्य समाहित हैं।

क्या प्रो-मैच्योर डिलोवरों के वायु प्रदूषण जिम्मेदार है ?



A portrait photograph of a middle-aged man with dark hair, wearing a bright red V-neck sweater over a plaid shirt. He is looking slightly to his left.

बढ़ रही है, तथा जहां पर प्रदूषण कम है, वहां स्थिति बेहतर है। रिसर्च से पता चलता है कि वायु प्रदूषण जन्म से पूर्व और जन्म के उपरांत जटिलताओं का कारण बन रहा है। शयद यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से महिलाओं में स्वाभाविक प्रसव बहुत कम होता है तथा महिलाओं में प्रसव के दौरान आजे वाली कठिनाइयों से बचने के लिए सिजेरियन ऑपेरेशन कर दिए जाते हैं। कहना शर्त नहीं होगा कि आज ज्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का असर न केवल भारत पर अपेक्षित संपूर्ण विश्व पर पड़ रहा है। अत्याधिक गर्भी, असीमित वर्षा(आतिवृष्टि) भी बच्चों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। आज हमारे देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में वायु प्रदूषण कहीं अधिक है। इसलिए नवजातों की सेहत पर बड़ा खतरा मंडरा है। स्पष्ट है कि यह समस्या केवल विकित्सा से ही हल नहीं होगी। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को खत्म करके ही हम बच्चों के सामान्य जन्म की उम्मीद कर सकते हैं। इस क्रम में शोधकर्ताओं ने देश में विशेष रूप से उत्तरी राज्यों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को तेज करने की मांग की है। औरतलब है कि 2019 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम भारत में वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए पीएम प्रदूषकों के स्तरों को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। अंत में, यही कहांगा कि आज ज्लोबल वार्मिंग के साथ ही जलवायु परिवर्तन पर हमें समय रहते ध्यान देना होगा और विभिन्न मानवीय गतिविधियों (अंधाधृत विकास-यथा औद्योगिकीकरण, शहरीकरण) को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना होगा। पर्यावरण है तभी जीवों का अस्तित्व है, पर्यावरण नहीं तो कुछ भी नहीं है। आज देश में जलवायु अनूकूलन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता महत्ती है। हमें धरती पर जल प्रबंधन व इसके संरक्षण पर ध्यान देना होगा। जीवाशम ईंधन के विकल्प दूढ़कर आगे बढ़ाना होगा। वायु गुणवत्ता नियंत्रण को भी स्वास्थ्य नीति का अहम हिस्सा बनाना होगा। वायु प्रदूषण कम करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास और सामूहिक पहल शामिल हैं। मुख्य रूप से, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना, और अधिक पेड़ लगाना(वृक्षारोपण करना), पेड़ों की अंधाधृत कटाई पर रोक जैसे उपाय वायु प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं। हमें औद्योगिक उत्पादन को कम करना होगा। साथ ही साथ, शहरी नियोजन में सुधार, प्रदूषण नीतियों को पूरी ईमानदारी से लागू करना, तथा प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर ही प्री-मैच्योर डिलीवरी और कम वजन के नवजात की समस्या से निपटा जा सकता है।

लाखा गावा म सहकारा संस्थाए,

इडुप्पिलाइजर का आपाराटिव लामटड (इफका) उवरका के उत्पादन और विपणन में विश्व में खासा स्थान रखती है। कृषकों यानी कृषक भारती सहकारी लिमिटेड किसानों को उर्वरक, बीज और अन्य कृषि इनपुट उपलब्ध करवाती है तो श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ उत्पादन से महिलाओं को सशक्त बनाती है। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड यानी 'एपेक्स बैंक' राजस्थान में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की शीर्ष संस्था है। इन सबका प्राथमिक संबंध गाँवों और ग्रामीणों से है।



हरीश शिवनार्न

शाह की मानें तो 2030 तक इनमें से हर गाँव में सहकारी संस्था बन जाएगी। सवाल यह है कि भारत के आधारभूत ढांचे और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य बातों को देखते हुए क्या यह व्यावहारिक रूप से संभव है? दरअसल इस शाही लक्ष्य की प्राप्ति में इतनी चुनौतियां, समस्याएँ हैं कि शाह के लिए यह राह आसान नहीं है। मुख्य चुनौतियों को कुछ बिंदुओं में समझा जा सकता है बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में खाराब करनेकर्तवी, बिजली और इंटरनेट की कमी के कारण आधुनिक तकनीकों को अपनाना चुनौतीपूर्ण है। सहकारी समितियों को बाजार तक पहुंचने और सप्लाई चैन सिस्टम में तकनीकी पिछापान प्रमुख बाधा है। वित्तीय संसाधन का टोटा सहकारी संस्थाओं को स्पायिट करने और संचालित करने के लिए पर्याप्त पूँजी की आवश्यकता होती है। ग्रामीण सहकारी समितियों के पास अक्सर सीमित वित्तीय संसाधन होते हैं। सरकारी फार्डिंग पर अत्यधिक निर्भरता और निजी निवेश की कमी बड़ी चुनौती होती है। प्राइवेट सेक्टर से प्रतिस्पर्धा सहकारी समितियां अक्सर बड़े व्यवसायों और निजी क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असर्मर्थ रहती हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बाजार तक

पहुंच सीमित है। बुनियादी ढांचे की कमी, जैसे गोदामों और परिवहन सुविधाओं का अभाव, उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मुख्य बाधा है। सीमित दायरा और एकल उद्देश्य कई सहकारी समितियों के बीच एक या दो ग्रांवों तक सीमित हैं और एकल उद्देश्य (जैसे केवल ऋण प्रदान करना) पर काम करती हैं, जिसके कारण उनकी सासाधन क्षमता और प्रभाव सीमित रहता है। केंद्र और राज्य की नीतियों का संघर्ष सहकारी समितियाँ राज्य सूची का विषय हैं, जिसके कारण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी एक बड़ी बाधा है। नई नीतियों और कानूनों, जैसे मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम 2023 को लागू करने में भी कई जटिलताएं हैं। राजनीतिकरण मुख्य बाधा सहकारी संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारी प्रायः किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े ही होते हैं। अक्सर राजनेताओं ने समझदारी के कल्याण की कीमत पर अपने राजनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों का दुरुपयोग भी किया है। सहकारी समितियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतात्त्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया का अभाव है। राजनीतिक हस्तक्षेप और नौकरशाही नियंत्रण समितियों की स्वायत्ता को कमज़ोर करते हैं। इन चुनौतियों को देखते कहा जा सकता है कि यह लक्ष्य एक हिमालयन टास्क है। इसके सियासी खतरे भी बहुत हैं। इससे मोदी-शाह की साख के साथ भाजपा का अविष्य भी जुड़ा है। इसकी सियासी गणित इस बात से समझी जा सकती है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को जिस मुख्य कारण ने पूर्ण बहुमत से रोक दिया था ग्रामीण मतों में गिरावट। ग्रामीण इलाकों से भजपा को 35 प्रतिशत वोट मिले, जो 2019 के 39.5 से 4.5% कम थे। गठबंधन की दृष्टि से देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में एकड़ीए को प्रति 100 मतदाताओं में से 43 वोट मिले, जबकि इडिया गठबंधन को 42 वोट मिले। फ़ासला भले ही एक फ़ीसदी का हो लैकिन लाखों समितियों के गठन में कोई भी चूक असंतुष्ट उपजाने में पर्याप्त है और कोई भी उलटफेर बड़ी चुनौती बन सकता है।

